भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 221

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट डेटा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

221. श्री आदित्य यादवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में कारपोरेट डेटा प्रबंधन (सीडीएम) योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रतिभाशाली तकनीकी कर्मचारियों की सुरक्षा के विषय में उत्पन्न चुनौतियों पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा वेतन संरचना में संशोधन, कौशल बढ़ाने और योजना की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए प्रस्तावित या उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क), (ख) और (ग): जी नहीं। कारपोरेट डेटा प्रबंधन (सीडीएम) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे मंत्रालय के अधीन आंतरिक डेटा माइनिंग और विश्लेषण सुविधा स्थापित करने के लिए क्रियान्वित किया गया है। इस स्कीम का उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले सहित किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस योजना का कोई क्षेत्रीय कार्यान्वयन नहीं है।

*****